आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका
(बिलासपुर जिले के संदर्भ में)

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ से जनसंचार एवं पत्रकारिता विषय में पी–एच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध संक्षेपिका

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करूणा
ESTABLISHED 1996

शोधार्थी

गुरु सरन लाल

नामांकन संख्याः 410/09

शोध–पर्यवेक्षक

डॉ. रचना गंगवार

असिस्टेंट प्रोफेसर

जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

2015

भारतवर्ष अनेकता में एकता का देश है। यहां अनेक जाति, धर्म और सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं। इन विभिन्न जाति, धर्म और सम्प्रदाय के बीच जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले समुदाय भी हैं जो शहरों की चकाचौंध से मीलों दूर व विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जिनके लिए यह तय कर पाना मुश्किल है कि आने वाले कल की भोजन सामग्री कहां से और कैसे प्राप्त की जाए ? ये वे अनुसूचित जनजाति के अशिक्षित लोग हैं जिन्हें आदिवासी कहा जाता है।

भारत में अनेक प्रकार की अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं जिनमें प्रमुख हैं–संथाल,गोंड,भील,बेगा, शहरिया आदि। भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि प्रदशों में आदिवासी बहुतायत में निवास करते हैं। इन सभी जनजातियों के समूल विकास के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारें अनेकानेक योजनाएं संचालित करती रही हैं और कर रही हैं। इसके बावजूद भी वास्तविक स्थिति यह है कि आदिवासी आज भी विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश के दक्षिण–पूर्व दिशा में अवस्थित है। मध्य प्रदेश से ऐसी स्थिति के कारण ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के पूर्वांचल की संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं देश के छह राज्यों से घिरी हुई हैं। ये राज्य हैं–उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर–पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, दक्षिण–पश्चिम में आन्ध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा तथा उत्तर–पूर्व में झारखण्ड स्थित है।छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में $17^{0}48'$ उत्तरी अक्षांश से 24^{0}

उत्तरी अक्षांश तथा 80°14′ पूर्वी देशान्तर तक विस्तृत है। इसकी आकृति समुद्री घोड़े (Sea Horse) के समान है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग कि.मी. है जो भारत के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत है एवं मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.48 प्रतिशत है। प्रदेश की भौगोलिक सीमा से कहीं भी समुद्र स्पर्श नहीं करता तथा समुद्र से इसकी सीमाएं लगभग 400 कि.मी. दूर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है जो महाराष्ट्र राज्य की सीमा के समीप स्थित प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नगर है। रायपुर स्थित दुधारी मंदिर तथा कनकली मंदिर 17 वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' भी कहा जाता है क्योंकि यहां धान की अत्यधिक पैदावार होती है। इस राज्य का गठन एक लम्बी प्रक्रिया के उपरांत हुआ है। राज्य का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा 01 नवंबर, 2000 को हुआ तथा यह देश का 26 वां राज्य बना। राज्य की राजधानी रायपुर समस्त प्रशासनिक वं राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र है। इसके अतिरिक्त प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को 4 संभागों एवं 16 जिलों में विभक्त किया गया है। फिर इन जिलों को 96 तहसीलों एवं 146 विकास खण्डों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, कोरबा, उरॉव, हल्वा, भतरा, कॅवर, कमार, माडिया आदि जनजातियां निवास करती हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में बिलासपुर जिले की कुल 8 तहसीलों बिलासपुर, बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर, पेंड्रा, गौरेला और मरवाहीआदिवासी विकास और उसमें मीडिया की भूमिका का अध्ययन किया गया। निर्धारित क्षेत्र में विकास की स्थिति तथा उसमें मीडिया के योगदान का अध्ययन किया गया। आदिवास विकास में मीडिया का योगदान कितना कारगर है, का

अध्ययन किया गया और आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका का परीक्षण करने की कोशिक की गई है।

नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुतायत में निवास करते हैं। कुल जनसंख्या की 32.5 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है। आदिवासी समाज की अपनी समृद्ध परंपराएं हैं। उनका रहन–सहन, खान–पान आज भी मुख्य समाज से भिन्न है। विकास के निर्धारित मानकों को प्राप्त करने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। आदिवासी समाज के संदर्भ में देखा जाए तो एक तरफ जहां आदिवासी समाज की अपनी समृद्ध परंपराएं हैं वहीं आदिवासी समाज में अशिक्षा, असमानता, अंधविश्वास, बेरोजगारी जैसी तमाम विसंगतियां भी हैं। जब विकास की बात आती है तो मीडिया से विशेष रुप से आशाएं की जाती हैं कि वह विकास में वांछित सहयोग करे। इस शोध में आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका का परीक्षण करने की कोशिश की गई है।

प्रस्तुत शोध में हमने यह परिकल्पना की थी कि निर्धारित आदिवासी क्षेत्र में मीडिया की कवरेज बहुत कम है। मीडिया का इन आदिवासी क्षेत्रों में कम कवरेज होने के कारण, मीडिया आदिवासी क्षेत्रों के विकास में पर्याप्त भूमिका नहीं निभा पा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए मीडिया द्वारा कोई अभियान या एजेंडा बनाकर रिपोर्टिंग करने का अभाव दिखता है। क्योंकि रूटीन रिपोर्टिंग से हटकर मीडिया को कुछ निर्धारित दिशा में प्रयास करने होंगे ताकि आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो।षोध के परिणाम में तीनों ही परिकल्पनाएं सही पाई गईं।

शोध के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का चयन किया गया था। बिलासपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 8270 वर्ग कि.मी. है। जनगणना–2011 के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 19,61,922 है । जिले की कुल साक्षरता दर 62.2 प्रतिशत है। जिले में कुल 8 तहसीलें है। जिनके नाम हैं–बिलासपुर, बिल्हा, पेंड्रारोड, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा, मरवाही एवं गौरेला। जिले में लोकसभा की सीट बिलासपुर है तथा 10 विधानसभा क्षेत्र हैं।

बिलासपुर जिले में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 4,25,688 है, जिनमें से 2,11,994 पुरुष एवं 2,13,694 महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 3,83,705 जबकि नगरीय क्षेत्रों में कुल 41,883 अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते हैं ।

बिलासपुर में हिन्दी भाषा के दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नवभारत, हरिभूमि, देशबंधु, हाइवे चैनल, तरुण पथ, स्वदेश, इवनिंग टाइम्स, प्रखर संदेश, लोक स्वर आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। अंग्रेजी माध्यम के समाचार पत्रों में 'द हितवादा' का स्थानीय संस्करण एवं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स और द हिन्दू समाचार पत्रों के राष्ट्रीय संस्करण उपलब्ध होते हैं। बिलासपुर में आकाशवाणी के प्रसारण सुनवाये जाते हैं और दूरदर्शन के कार्यक्रमों को रायपुर से रिले करके दिखाया जाता है। साथ ही निजी क्षेत्र के आईबीसी–24, सीसीएन–अभी तक, ईटीवी, सिटी चैनल, ग्रांड चैनल और साधना चैनल का प्रसारण किया जाता है। बिलासपुर में एक मात्र निजि रेडियो चैनल **माई एफ.एम.** है, जो यहां के युवाओं के आकर्षण का केन्द्र है। बिलासपुर के डॉ. सीवी रमन विष्वविद्यालय में 'रमन रेडियो' सामुदायिक रेडियो संचालित है। बिलासपुर में www.raviwar.com का क्षेत्रीय कार्यालय है। इस वेबसाइट पर समसामयिक घटनाओं और परिदृश्य पर समाचार, लेख और फीचर होते हैं। साथ

ही साहित्यिक समाचार, साहित्यिक रचनाएं और साहित्यिक पुस्तकों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। बिलासपुर में वर्तमान में 4 सिनेमाघर है। बिलासपुर में दो बड़े मॉल हैं–रामा मैग्नेटो मॉल और 36 मॉल। दोनों मॉल में फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं।

शोध में सर्वेक्षण शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया। उत्तादाताओं से ऑकड़ों के संकलन के लिए अनुसूची एवं मीडिया प्रोफेशनल्स से साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। बिलासपुर जिले के कुछ 8 तहसीलों बिलासपुर, बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर, पेंड्रा, गौरेला और मरवाही में से कोटा, तखतपुर, मरवाही और बिलासपुर तहसीलों के गांवों में निवासरत आदिवासियों पर सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। कुल 400 उत्तरदाताओं से अनुसूची के माध्यम से ऑकड़ों का संकलन किया गया।

छत्तीसगढ़ में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, परंपरागत माध्यम और न्यू मीडिया का संजाल बिछा हुआ है। विकास के विभिन्न विषयों और मुद्दों को मीडिया द्वारा समय–समय पर उठाया जाता है। सरकार की नीतियों, योजनाओं, विकास कार्यक्रमों इत्यादि का प्रचार–प्रसार मीडिया द्वारा किया जाता है। लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के साथ–साथ जनजागरूकता फैलाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन दूरदराज के क्षेत्रों में जहां मीडिया की पहुंच नहीं है या कम है वहां विकास में दिक्कतें आ रही हैं।

विकास पत्रकारिता का उद्देष्य केवल विकास योजनाओं और नीतियों का प्रचार–प्रसार करना ही नहीं होता बल्कि उनके क्रियान्वयन और लक्षित समूह तक इसकी पहुंच को भी

सुनिष्चित करना होता है। छत्तीसगढ़ की सामाजिक और राजनीतिक बनावट में खामियों के कारण विकास योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार व क्रियान्वयन में दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही विभिन्न चुनौतियों जैसे–नक्सलवाद, भ्रष्टाचार आदि के कारण भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन में रूकावटें आ रही हैं। मीडिया जनता और सरकार के बीच सेतू का कार्य करती है। मीडिया विभिन्न असंतुष्ट समूहों और सरकार के बीच संपर्क का माध्यम बन सकता है लेकिन अफसोस कि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। कुछ प्रयास अवश्य जारी हैं, लेकिन ये नाकाफी हैं। मीडिया को एक सुनिश्चित रणनीति बनानी होगी। समाज के कमजोर, बंचित वर्ग व समूहों को साथ में मिलाकर विकास की बात की जानी चाहिए।

शोध का परिणामः

सर्वेक्षण में प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि आदिवासी लोगों तक सूचना प्रदान करने में मुख्यधारा की मीडिया की अपेक्षा परंपरागत माध्यम अधिक कारगर हैं। अधिकतर आदिवासियों को सूचनाएं परंपरागत माध्यमों, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, सरपंच, ओपिनियन लीडर के माध्यम से प्राप्त होती हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी इन्हीं माध्यमों से मिलती है। बहुत ही कम लोगों ने कभी शासन–प्रशासन की किसी तरह की षिकायत मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। अधिकतर लोगों का कहना है कि उन्हें मीडिया द्वारा कभी किसी तरह की ऐसी मदद नहीं मिली है जो उनके विकास के लिए सहायक हो। अधिकतर लोगों को नहीं लगता है कि उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने में मीडिया सहायक है। ऐसे लोग भी बहुत कम हैं जिन्होंने मीडिया में सहभागिता की है। जिन लोगों ने सहभागिता की है, उन्होंने

परंपरागत माध्यम जिनमें लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, नुक्कड़नाटक, कठपुतली नृत्य आदि में सहभागिता की है या किसी घटना या दुर्घटना होने पर टेलीविजन पर दिखाये गये हैं।

अधिकतर गांवों में पत्रकार आते ही नहीं। कुछ जगहों पर महीने में एक बार और कहीं कभी–कभी आते हैं। इससे स्पष्ट है कि इन आदिवासी इलाकों में मीडिया की कवरेज नहीं के बराबर है। अधिकतर गांवों में सरकारी अधिकारी जैसे कलेक्टर, एस.डी.एम., डीपीओ, खण्ड विकास अधिकारी आदि भी नहीं आते हैं। कुछ गावों में महीने में एक बार आते हैं और कुछ गावों में कभी–कभार आते हैं। बहुत कम संख्या में आदिवासी लोग सरकार द्वारा आयोजित लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनृत्य इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं। वहीं दूसरी ओर अधिकतर लोगों ने बताया कि उनके गांव में व्यक्तिगत रूप से आयोजित लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनृत्य इत्यादि कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं। अधिकतर लोगों ने बताया कि उन्हें किसी सरकारी योजना जैसे–मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, वृद्धा पेंषन योजना इत्यादि का लाभ मिला है। अधिकतर लोग अपने उत्पाद जैसे सब्जी, फल, अनाज इत्यादि स्थानीय बाजार में बेचते हैं। कुछ लोग बिचौलिए को और कुछ सरपंच, ओपिनियन लीडर द्वारा सुझाए गये किसी व्यक्ति को। आदिवासी लोगों को उनके उत्पाद का बाजार मूल्य स्थानीय बाजार से, बिचौलिए से या गांव के किसी व्यक्ति से पता चलता है।

अधिकतर लोगों ने बताया कि उनके गांव में विकास के लिए कोई गैर सरकारी संगठन या स्वयं सहायता समूह कार्य नहीं करता। मात्र एक प्रतिषत लोग सामुदायिक रेडियो के बारे में जानते हैं। उनमें से भी बहुत कम लोग सामुदायिक रेडियो से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं। इन इलाकों के अधिकतर लोग समाचार–पत्र, रेडियो, टेलीविजन जैसे जनसंचार के

माध्यमों की अन्तर्वस्तु से परिचित नहीं हैं। अधिकतर लोगों का मानना है कि उनके सामाजिक मुद्दे जैसे भूमि अधिग्रहण, जंगल, जमीन, पानी इत्यादि को मीडिया में पर्याप्त कवरेज नहीं मिल पाता है। साथ ही यह भी मानना है कि उनकी सामाजिक समस्याएं जैसे टोनही प्रथा, बाल विवाह इत्यादि के निराकरण में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। इस प्रष्न पर कि आपको सरकार से किस तरह के विकास की अपेक्षा है, आदिवासी लोगों ने बताया कि वे सरकार से समग्र विकास की अपेक्षा रखते हैं। ऐसा विकास जिसमें उन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ शिक्षा, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए वे विशेष योजनाओं के संचालन की मांग करते हैं। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि उनकी स्थिति के बदलाव में मीडिया कोई भूमिका नहीं निभा रहा है। अधिकतर लोगों का मानना है कि मीडिया उनके विकास सम्बन्धी मुद्दों को सरकार तथा आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग नहीं कर रहा है। अधिकतर लोगों का कहना है कि लोक माध्यमों द्वारा उनकी समस्याओं को सही तरीके से नहीं उठाया जाता। अधिकतर उत्तरदाता ये मानते हैं कि अन्य माध्यमों की तुलना में लोक माध्यम उनके समुदाय में संचार के लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। वहीं अधिकतर लोगों को यह भी दुख है कि उनके क्षेत्र में लोक माध्यमों द्वारा किसी तरह का जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया।

प्रस्तुत शोध आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका के महत्व को प्रतिपादित करता है। यदि मीडिया आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार तथा नीति निर्माताओं के समक्ष दृढ़ता से उठाये तो आदिवासी क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिल सकती है।